Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to monitor the financial health of various Nationalised Banks and take appropriate action to prevent their closure.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) ः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार देश के 9 सरकारी बैंक ऐसे हैं, जो बंद होने की स्थिति में हैं। फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आई.डी.बी.आई. बैंक और यूको बैंक को प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया है अर्थात् यह दोनों बैंक अब किसी को भी कोई लोन नहीं दे सकते हैं।

इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आध्र बैंक भी जल्दी ही प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन में डाले जाने वाले हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 144 लाख करोड़ का है और बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 70 लाख करोड़ का है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस दिए गए ऋण में से 13 लाख करोड़ डूबने की पूरी संभावना है और इस 13 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ वो ऋण है जो विभिन्न बैंकों ने अलग-अलग 10 कम्पनियों को दिया है। इसमें भूषण स्टील को 90 हजार करोड़, विडियोकोन को 58 हजार करोड़, जे.पी. ग्रुप को 55 हजार करोड़, एस्सार लिमिटेड को 50 हजार करोड़, जिंदल ग्रुप को 38 हजार करोड़, लेन्को को 19 हजार करोड़, पुंज लॉयड को 14 हजार करोड़ और एल्क्ट्रो स्टल को 14 हजार करोड़ रूपये ऋण दिया गया है। यदि ये बैंक बंद होते हैं तो इनके ग्राहकों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इन ग्राहकों की जमा की गई राशि का क्या होगा, यह एक चिंता का विषय है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन बैंकों की हालत पर नजर रखी जाये और इन बैंकों को बंद होने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।